पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन समाप्त

कैम्प कार्यालय लखनऊ, रविवार, 1 फरवरी, 2015 : भारत में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों का 77वां सम्मेलन, जिसका उद्घाटन लोक सभा की माननीय अध्यक्ष और सम्मेलन की चेयरपर्सन श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा किया गया था, का आज समापन हुआ।

सम्मेलन के समापन पर प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए लोक सभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कार्यसूची की दोनों मदों पर चर्चा के उच्च स्तर को लेकर पीठासीन अधिकारियों की सराहना की। कार्यसूची की पहली मद *अर्थात् लोकतंत्र में संसद की भूमिका* पर होने वाली चर्चा में 17 पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। यह सत्र 2 घंटे 26 मिनट तक चला और इसमें बहुत गहन और सार्थक चर्चाएं हुई। पीठासीन अधिकारियों में इस विचार को लेकर मतैक्य था कि विधायी निकायों को राष्ट्र निर्माण विशेष रूप से सरकारी नीतियों और विधानों खासतौर पर जिनका संबंध सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी विषयों से है, की पूर्णतः संवीक्षा के माध्यम से और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने आगे बताया कि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पीठासीन अधिकारियों का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी नीतियों से पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति भी लाभान्वित हो। लोक सभा की माननीय अध्यक्ष ने संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संवर विधान सभा क्षेत्र के पोटलोड गाँव को गोद लिया है। वह वैकल्पिक ऊर्जा, स्त्री-पुरुष समानता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं। उन्होंने गाँव के विकास हेतु एक जैसे समूहों का निर्माण भी किया है। विकास के साथ-साथ वह लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए ग्रंथालयों की स्थापना कर उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करने हेतु भी पहल कर रही हैं।

कार्यसूची की दूसरी मद अर्थात् *पेपरलेस संसद* पर चर्चा आरंभ करते हुए और सत्र के परिणाम के बारे में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लोक सभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने इस बात को नोट किया कि सभी पीठासीन अधिकारियों में कम से कम इस बात पर सहमति बनी है कि कागज के उपयोग में इस बात का ध्यान रखते हुए यथासंभव कमी लाई जाए कि यह पर्यावरण अनुकूल होने के साथ-साथ वित्तीय दृष्टिकोण से भी बुद्धिमत्तापूर्ण पहल होगी। उनका स्वप्न है कि दूर-दूर तक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षितिज का विस्तार हो ताकि एक बटन दबाकर दूरस्थ क्षेत्र तक ज्ञान का प्रवाह हो सके।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने महसूस किया कि चूँकि प्रस्ताव पारित हो चुका है अतः सभी पीठासीन अधिकारी अब अपने-अपने विधानमंडलों को पेपरलेस संस्था बनाने के अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पेपर का अपेक्षाकृत न्यून प्रयोग करने संबंधी अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे। इससे पूर्व प्रातःकाल सम्मेलन का कार्यसत्र पुनः आरंभ हुआ और कार्यसूची की दूसरी मद अर्थात *पेपरलेस संसद* को चर्चा के लिए लिया गया। गोवा विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने चर्चा आरंभ की। 11 पीठासीन अधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया और यह चर्चा 2 घंटे 35 मिनट तक चली।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने भी समापन सत्र को सम्बोधित किया। कार्यसूची के विषय, जिन पर सम्मेलन में सार्थक चर्चाएं हुई हैं, का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह अनिवार्य है कि राज्य विधानमंडल और संसद लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए अपनी-अपनी भूमिका का प्रभावी रूप से निर्वाह करें। अपेक्षाकृत अधिक त्वरित विकास को बढ़ावा देने तथा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने का उपबंध करने के उद्देश्य से वांछित विधानों के अधिनियमन से लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि पेपरलेस संसद की दिशा में आगे बढ़ने के निर्णय में बहुत से आश्वासन अंतर्निहित हैं। विधानमंडलों में कागज के उपयोग में प्रभावी रूप से कमी और अन्य संगठनों में भी इसी तरह के परिवेश के निर्माण से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव जो कागज के उत्पादन के कारण उत्पन्न होता है, को कम करने में सहायता मिलेगी।

सम्मेलन का समापन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माननीय सभापति श्री गणेश शंकर पाण्डेय के धन्यवाद प्रस्ताव से हुआ।